is envisaged that such borrowers are to repay the bank-loan instalments from the income generated from their productive ventures/business/occupation and not from the compensation received from the Government. The banks follow-up with the borrowers the payment of instalments as and when they fall due according to the repayment schedule. However, specific complaints, if any, could be taken up with the concerned bank for remedial action. Relief in the repayment of bank loans can also be considered by banks on the merits of each individual case.

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा राजभाषा का प्रयोग

1041. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी-कितनी शाखाएं प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं और इन शाखाओं में राजभाषा के प्रयोग संबंधी स्थिति क्या है ;

(ख) राज्यों में स्थित प्रत्येक बैंक की ऐसी शाखाओं की संख्या कितनी-कितनी है, जो अपना 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत कार्य राजभाषा हिन्दी में करते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी स्थिति क्या है और क्या इस संबंध में योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में "ग" समूह के राज्य अन्य राज्यों से आगे हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में राजभाषा संबंधी कार्यक्रम का क्रियान्वयन धीमा है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या 28 है और न कि 29 जैसे कि प्रश्न में बताया गया है । दिनांक 30 जून, 1986 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्य/संघ राज्य-वार शाखाओं की संख्या की सूची संलग्न विवरण में दी गई है

[नीचे देखिए]

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली में राजभाषा के प्रयोग के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है अलबत्ता, राजभाषा नियम, 1976 में परिभाषित भाषाई क्षेत्रों अर्थात् "क", "ख" और "ग" के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है ।

उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा के प्रयोग की स्थिति अलग-अलग है । लेकिन कुल मिलाकर, सरकारी क्षेत्र के बैंक सभी क्षेत्रों में सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं । सरकार ने निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित करने के वास्ते सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अनुदेश दे दिए हैं :—

(i) उत्तर प्रदेश सहित "ख" क्षेत्र के राज्यों में बैंक शाखाओं में अधिकांश काम हिन्दी मे किया जाये ।

(ii) उत्तर प्रदेश तथा "ख" क्षेत्र के अन्य राज्यों में पास बुकें हिन्दी में जारी की जायें ; और

(iii) "क" क्षेत्र में स्थित बैंकों के प्रधान कार्यालयों में हिन्दी अनुभाग के अलावा एक अनुभाग को अपना सारा काम हिन्दी में करने के वास्ते नामित किया जाए ।

विवरण

30 जून, 1986 तक राज्य-वार बैंक कार्यालयों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	4130
2	असम	975
3	बिहार	4229
4	गुजरात	3085
5	हरियाणा	1111
6	हिमाचल प्रदेश	552
7	जम्मू और काश्मीर	727
8	कर्नाटक	3926
9	केरल	2724
10	मध्य प्रदेश	3737
11	महाराष्ट्र	4919
12	मणिपुर	67
13	मेघालय	130
14	नागालैंड	66
15	उड़ीसा	1735
16	पंजाब	2004
17	राजस्थान	2681
18	सिक्किम	19
19	तमिल नाडु	3930
20	उत्तर प्रदेश	7345
21	त्रिपुरा	136
22	पश्चिम बंगाल	3418
23	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14
24	अरुणाचल प्रदेश	54
25	चंडीगढ	107
26	दादर और नागर हवेली	6
27	दिल्ली	1059
28	गोवा दमन और दीव	260
29	लक्षद्वीप	5
30	मिजोरम	51
31	पांडिचेरी	63
	कुल	53265

Number of ex-armymen in the country

1042. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what is the total number of ex-armymen in the country, till December, 1986;

(b) what is the number of ex-armymen employed during the last two years as on date; and

(c) what is the number of ex-armymen employed in the Government service during the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI ARUN SINGH): (a) to (c) Separate figures of ex-armymen are not available.

There were about 43.73 lakhs of ex-servicemen as per information collected during the year 1985.

According to available information, the total number of ex-servicemen who got re-employment during the year 1985 was 23234. In regard to 1986, figures for the half year January to June only are available and for this period the number who got re-employment was 11,745.

The Central Government and State Governments have employed 20,781 and 10,358 ex-servicemen during the year 1985 and the half year January to June 1986 respectively.

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

1043. **श्री राधाकिशन मालवीय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य की कितनी बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनाएं योजना आयोग के पास लम्बित पड़ी हैं ।